बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 97

बैंकों की बारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसी हुई परिसंपत्तियों के निस्तारण के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। गत शुक्रवार को जारी किए गए इन नए मानकों के मुताबिक बैंकों को यह अधिकार है कि वे निस्तारण को अंजाम दे सकें। इसके साथ ही उन्हें इस दृष्टि से भी तैयार किया गया है कि संकटग्रस्त खातों को लगातार मदद के इरादे पर अंकुश लग सके। ऐसे कर्जदारों को कठोर कदमों का सामना करना होगा जिनमें उच्च प्रोविजनिंग और मौद्रिक जुर्माना भी शामिल हैं। आरबीआई ने अपने इस नवीनतम खाके में कहा है कि निस्तारण योजनाओं में असहमत कर्जदार के बकाये के नकदीकृत मूल्य के बराबर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरबीआई के 12 फरवरी के परिपत्र को खारिज किए जाने के बाद आए दबावग्रस्त परिसंपत्ति निस्तारण मानकों में सबसे अहम बात यह है कि अब बैंकों को यह निर्धारित करने के लिए 30 दिन की अवधि दी जा रही है कि कोई खाता गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) है या नहीं। पहले एक दिन की देरी पर डिफॉल्ट घोषित करने का कठिन और अव्यावहारिक मानक था। संशोधित परिपत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त बैंकों, नाबार्ड, एक्जिम बैंक और सिडबी को निस्तारण का मंच देता है।

मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि अधिकांश मामलों को नए तय मानकों के अधीन निपटाना चाहिए और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को अंतिम विकल्प के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। एक ओर जहां कर्जदारों को सक्रिय रहना होगा वहीं आरबीआई बैंकों को विशिष्ट डिफॉल्टरों के मामले में ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित करता रहेगा। कुल मिलाकर बैंकों पर दबाव बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें अनिवार्य तौर पर इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर करने होंगे। आईसीए का कोई भी निर्णय मान्य होगा अगर वोटिंग अधिकार के मुताबिक 75 फीसदी या कुल तादाद के आधार पर 60 कर्जदार उस पर सहमत हों। बैंकों को अब अपनी आंतरिक नौकरशाही में बहुत तेजी से काम करना होगा।

अगर निस्तारण योजना बनाने में विफलता हाथ लगती है तो प्रोविजनिंग में 35 फीसदी का इजाफा हो जाएगा, अगर 180 दिन की तय अवधि में यह काम नहीं कर पाती तो 20 फीसदी प्रोविजनिंग और अगर एक साल के भीतर कोई निस्तारण नहीं हो पाता तो 13 फीसदी की अतिरिक्त प्रोविजनिंग की जाएगी। अतिरिक्त प्रोविजनिंग के रूप में जो कीमत चुकानी होगी वह उन सरकारी बैंकों के लिए चिंता का विषय होगी जिनमें हाल ही में पूंजी डाली गई है। यह उन बैंकों के लिए भी समस्या बनी रहेगी जो आरबीआई की त्वरित सुधार कार्रवाई योजना के अधीन हैं। परंतु इस बात की संभावना नहीं है कि अधिक विवेक से काम करने वाले बैंक इस बढ़ी हुई प्रोविजनिंग से बिना वजह परेशान होंगे क्योंकि वे तो पहले ही अपने जोखिम के लिए उचित कदम उठा चुके होंगे। एक ओर जहां केंद्रीय बैंक के मानक 2,000 करोड़ रुपये की देनदारी चूकने वालों पर तत्काल लागू होंगे वहीं 1,500 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये तक के लिए इसकी शुरुआत एक जनवरी 2020 से होगी। ऐसे रुख ने बैंकों के बीच कई तरह की चिंताओं को जन्म दिया है। ये बैंक 2,000 करोड़ रुपये से कम के ऋण के लिए किस तरह की पहल करेंगे इसे देखना होगा। छोटे बैंक इस पहलू को लेकर काफी चिंतित हैं।

नए मानकों की सबसे बेहतर बात यह है कि वे 12 फरवरी के परिपत्र की मूल भावना को बरकरार रखते हैं और एक ऐसी व्यवस्था की पेशकश करते हैं जो निस्तारण को बहुमत का आधार देती है। अब यह दायित्व बैंकों पर है कि वे निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करें क्योंकि पिछले परिपत्र ने 70 बड़े कर्जदारों के करीब 3.8 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ऋण को प्रभावित किया।

विनय सिन्हा

यह केवल क्रिकेट नहीं है 'कैप्टन कूल'

धोनी को अपनी रेजिमेंट को क्रिकेट की पिच पर नहीं ले जाना चाहिए। खिलाड़ी जीत के लिए खेलकर देश को गौरव दिलाता है, वह सेना के दूत के रूप में ऐसा नहीं करता।

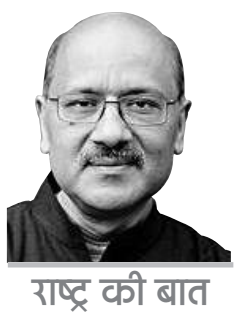

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

हम इस पुरानी समझ पर सवाल नहीं उठा सकते कि राजनीति बांटती है और खेल जोड़ता है। विश्वकप के इस मौसम में तो यह उक्ति और सही प्रतीत होती है। भारत दो बार क्रिकेट विश्वकप जीत भी चुका है। परंतु इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है: खेल लोगों को जोड़ता है लेकिन केवल उन्हें जो किसी एक पक्ष के समर्थक होते हैं। हम भारतीय अपनी टीम के पीछे खड़े होते हैं तो अन्य लोग अपनी टीम के। यहीं पर बात आती है महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग दस्तानों को लेकर छिड़े विवाद की, जिस पर भारतीय सैन्य बलों में से एक का प्रतीक चिह्न 'बलिदान' अंकित था।

खेल की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल (आईसीसी) ने इस पर आपत्ति जताई। आईसीसी के नियमों के तहत किसी खिलाड़ी द्वारा अपने शरीर या अपनी वस्तुओं पर किसी धार्मिक, राष्ट्रीय या वाणिज्यिक चिह्न या लोगो धारण करने की एक सीमा है।

उदाहरण के लिए प्रायोजकों के लोगो इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्हें आईसीसी मंजूरी देता है। इसके अलावा संबंधित देश के महासंघ का लोगो लगाया जा सकता है। अनुमति के मुताबिक राष्ट्रीय चिह्न धारण किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज को मंजूरी नहीं है। सैन्य प्रतीक तो कतई नहीं प्रयोग किए जा सकते। यह खेल का मैदान है, जंग का नहीं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कहना है कि उसने आईसीसी से अपील की है वह धोनी को रियायत दे दे। जनमत धोनी के समर्थन में है। इस बारे में विचार कीजिए: भारतीय टीम विश्वकप में है, धोनी उसका हिस्सा हैं, दूसरी ओर हमारे साहसी सशस्त्र बल हैं जिनकी वीरता को हाल ही में विकी कौशल की फिल्म ने परदे पर अमर किया। भला कौन भारतीय होगा राष्ट्रवाद के इस तिहरे चुंबकीय आकर्षण से बचेगा।

परंतु किसी न किसी को कहना होगा कि आईसीसी सही कह रही है। धोनी को यह चिह्न हटाना चाहिए। खेल के प्रतिस्पर्धी मैदान में मरने-मारने के प्रतीक नहीं होने चाहिए। यही कारण है कि हममें से कुछ लोगों को साहस करके धारा के विपरीत तैरना होगा। खासकर उन लोगों को जो इस खेल को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि भारत जीते। अगर हमारे खेल संबंधी राष्ट्रवाद पर सवाल उठता है तो उठने दें। ईसा मसीह की पंक्ति यहां सटीक है: पिता, उन्हें माफ कर दो, वे (जो हमें देशद्रोही ठहरा रहे) नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।

पहले देखते हैं कि राष्ट्रवादी और उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। कमांडोनुमा चैनल पहले ही ऐसे हैशटैग चलाने लगे हैं जिनमें धोनी का समर्थन किया जा रहा है। पहली बात, हमें सशस्त्र बलों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, भारत को पाकिस्तान के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है इसलिए पाकिस्तानी जहां भी हों उन्हें संदेश दिया जाना चाहिए। और तीसरा, आप किसी को उसकी पसंद जाहिर करने से नहीं रोक सकते। धोनी विशेष बल के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और उन्होंने पैराशूट जंपिंग उत्तीर्ण करके यह प्रतीक हासिल किया है। उनसे उनकी रेजिमेंट का प्रतीक नहीं छीना जा सकता है।

तीसरे का उत्तर आसान है: उनकी रेजिमेंट देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल रही है। जब रेजिमेंट देश के लिए लड़ती है तो उसके जवान बीसीसीआई या हॉकी महासंघ या भारतीय ओलिंपिक महासंघ के प्रतीक नहीं धारण करते।

हमें सशस्त्र बलों और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए लेकिन यह कहना अनुचित होगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जो कर रहे हैं उसका विरोध हमारे खिलाड़ी लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड या ओवल में करें। विरोध राजनेता और राजनयिक तैयार करते हैं, युद्ध जवान लड़ते हैं, खिलाड़ी जीत के लिए खेलकर देश के लिए गौरव लाते हैं, खिलाड़ी की पोशाक में अपनी सेना का ब्रांड ऐंबेसडर बनकर नहीं।

यह खेल दोनों खेल सकते हैं। अगर एक भारतीय सेना की वर्दी में आ सकता है तो पाकिस्तानी भी। क्रिकेट का खेल दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। अगर इसमें सैन्य भावना जोड़ दी जाती है तो उसे जनता तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इससे खेल दुश्मनी में बदल जाएगा। हम ईरान और इराक के बीच युद्ध की कटुता को याद कर सकते हैं।

जॉर्ज ऑरवेल ने सन 1945 के अपने निबंध द स्पोर्टिंग स्पिरिट (खेल भावना) में लिखा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल युद्ध के समान ही है। उनके मुताबिक इसमें महत्त्वपूर्ण बात खिलाड़ियों का व्यवहार नहीं बल्कि दर्शकों का रुख है। इन दर्शकों के पीछे पूरे राष्ट्र को देखा जा सकता है। हमारे महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले खेले हैं, हालिया दिनों में उन्होंने जूझने का माद्दा दिखाया और उन्हें कहीं अधिक सफलता भी मिली है लेकिन ऐसा केवल खेल में हुआ है। मैदान के बाहर दोनों टीमें मित्रवत रही हैं। यहां तक कि एक दूसरे के परिवार और बच्चों के साथ आनंद लेते हुए भी नजर आए। अच्छी बात है कि अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है। बालाकोट में एक झड़प हुई थी जिसमें किसी की जान नहीं गई और उस बात को चार महीने बीत भी गए। सन 1971 में जब जंग लड़ी जा रही थी तब सुनील गावसकर और जहीर अब्बास ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व एकादश के लिए एक साथ बल्लेबाजी की थी। यह वह समय था जब वायुसेना अकसर कराची पर बमबारी के लिए उड़ान भरती। सन 1999 में जब दोनों टीमें इंगलैंड में विश्वकप खेल रही थीं तब करगिल की लड़ाई चल रही थी। तब भी दोनों टीमें सहज थीं। दोस्ताना रिश्ते थे, यहां तक कि गिरने पर एक दूसरे को उठाने और विरोधी टीम के बल्लेबाज के जूते के फीते तक बांधे गए। वहां कोई टाइगर हिल को लाना नहीं चाहता था।

सैन्य प्रतीक, वर्दियां, बिल्ले, पट्टे, तमगे, बैंड और परेड आदि अच्छे लगते हैं और जोश बढ़ाते हैं। उनके साथ एक बोझ यह भी होता है कि सफलता या नाकामी युद्ध में जीत हार के समान लग सकती है। 16 जून को मैनचेस्टर में होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले समेत किसी भी खेल में एक ही पक्ष जीतेगा और दूसरा हारेगा। क्या वह जंग में सेना की हार के समान होगा? अगर दोनों टीमें ओल्ड ट्रैफल्ड में सैन्य प्रतीक के साथ मैदान में उतरीं तो? उस स्थिति में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पुलिस कम पड़ जाएगी।

हम ऑरवेल की ओर लौटते हैं जिन्होंने कहा था, 'जब मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि खेल देशों के बीच सद्भावना बढ़ाते हैं और यह भी कि अगर लोग फुटबॉल, क्रिकेट या अन्य खेलों के मैदान पर मिलें तो आपस में जंग नहीं होंगी, तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता।' उन्होंने 1936 के बर्लिन ओलिंपिक का उदाहरण दिया। वह सही भी थे और गलत भी।

मानव सभ्यता विश्व युद्ध और शीत युद्ध से बहुत आगे निकल आई है। खेल के मैदान पर निरंतर मुलाकात ने पुरानी दुश्मनी कम करने में मदद की है। इससे खिलाड़ी, उनके प्रशंसक, परिवार और मित्रों आदि को एक दूसरे के बारे में अधिक जानने को मिलता है। लोगों में आपसी रिश्ते बनते हैं। कई बार वे अपनी हताशा भी निकाल लेते हैं।

अच्छी बात है कि आज उस नजरिये को न तो लोकप्रियता हासिल है, न उसे सही माना जाता है। परंतु ओलिंपिक से लेकर पिंगपांग और बास्केटबाल से क्रिकेट और फुटबॉल से लेकर हॉकी तक अत्यंत प्रतिस्पर्धी खेलों ने सैन्य शत्रुताओं की धार कुंद करने और दिमाग के घाव भरने का ही काम किया है।

यकीनन हम किसी व्यक्ति के सेना के प्रति समर्पण की कद्र करते हैं, खासतौर पर तब जबकि वह मानद रूप से वहां सेवारत रहा हो। उदाहरण के लिए धोनी पद्म पुरस्कार ग्रहण करने विशेष बल की पूरी वर्दी में और मरून रंग की टोपी पहनकर गए थे। यह बहुत अच्छा कदम था। राष्ट्रपति भी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। उन्हें अपनी रेजिमेंट को क्रिकेट के मैदान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। विकेट के पीछे उनका जुझारूपन कभी कम नहीं होगा। वह हर बार किसी बल्लेबाज को स्टंप या कैच करते वक्त उस प्रेरणा को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी हथेलियों पर सजाई। भले ही प्रतीक चिह्न हो या नहीं लेकिन विकेट के पीछे धोनी के दस्ताने सबसे खतरनाक बने रहेंगे।

राजकोषीय मोर्चे पर हुए जादू की कुछ और है हकीकत

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में केंद्र सरकार का पूरे वर्ष का शुद्ध कर राजस्व 13.17 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह चार माह पहले सरकार के अंतरिम बजट में प्रस्तुत अनुमान से 1.67 लाख करोड़ रुपये कम है। यह कमी मामूली नहीं है बल्कि जीडीपी के 0.9 फीसदी के बराबर है। इसके बावजूद सरकार वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 फीसदी रखने में कामयाब रही। यह चमत्कार कैसे हुआ?

सीजीए के आंकड़े कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। सरकार इसलिए बचाव में कामयाब रही क्योंकि ऋण अदायगी हुई और विनिवेश प्राप्तियां बजट से अधिक रहीं। इस प्रकार 2018-19 में कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्ति करीब 1.03 लाख करोड़ रुपये रही जबकि संशोधित अनुमान में इसके 0.93 लाख करोड़ रुपये रहने की बात कही गई थी। इससे कर राजस्व कमी 10,000 करोड़ रुपये तक घटी। गैर कर राजस्व में 1,000 करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी ने राजस्व में कुल कमी को 1.56 लाख करोड़ रुपये तक घटाया।

इसके बावजूद लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में सरकार ने व्यय में कटौती शुरू की। सबसे पहले उसने पूंजीगत व्यय कम करना शुरू किया। इसमें करीब 13,000 करोड़ रुपये की कमी की गई। अब कमी घटकर 1.43 लाख करोड़ रुपये रह गई थी। इसके बाद सरकार ने बजट से इतर उधारी या अपने ही व्यय को सरकारी संस्थाओं को स्थानांतरित करने और उन्हें राष्ट्रीय अल्प बचत फंड आदि से उधारी लेने की प्रक्रिया अपनाई। सरकार ने ऐसी बजट से इतर उधारी के लिए भारतीय खाद्य निगम, आवास एवं शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसे संस्थानों का रुख किया। ऐसा करके उसने खाद्य सब्सिडी, सस्ते आवास की योजना, सिंचाई, ग्रामीण आवास और विद्युतीकरण के व्यय की पूर्ति की। ऐसी उधारी की यह राशि 1.32 लाख करोड़ रुपये थी। सीजीए के आंकड़ों में यह उधारी शामिल नहीं है लेकिन इस चतुराईपूर्ण व्यय प्रबंधन को लेकर संकेत अवश्य है। उदाहरण के लिए 2018-19 में सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 1.02 लाख करोड़ रुपये है जो 1.71 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 69,000 करोड़ रुपये कम है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी बिल में 40 फीसदी कटौती कैसे की? उसने एफसीआई से कहा कि वह उधारी लेकर व्यय की पूर्ति करे। इसी तरह आवास, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए नाबार्ड, हुडको, एनएचबी और आरईसी से धन की व्यवस्था कर व्यय में 63,000 करोड़ रुपये की कमी की गई।

अब यह कमी घटकर 11,000 करोड़ रुपये रह गई थी। ऐसे में सरकार की उधारी आवश्यकता या राजकोषीय घाटा 6.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह कोई खास समस्या नहीं थी। वर्ष 2018-19 में जीडीपी का नॉमिनल आकार संशोधित कर 188.41 लाख करोड़ रुपये से 190.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे भी राजकोषीय घाटे को 3.4 फीसदी रखने में सहायता मिली।

वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तो हासिल हो गया लेकिन इसे हासिल करने के तरीके से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, वित्त मंत्रालय ने कर राजस्व के अनुमान में इतने गुंजाइश क्यों रखी? कर राजस्व अनुमान में 11 फीसदी की चूक शर्मनाक है। बजट की प्रस्तुति को चार सप्ताह पहले करने से योजनाओं के लिए व्यय की उपलब्धता तेज हुई लेकिन सरकार की वर्ष भर के कर राजस्व अनुमान की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। यह अगले वर्ष के अनुमान की विश्वसनीयता को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा।

उदाहरण के लिए अनुमानित और वास्तविक शुद्ध कर राजस्व में 11 फीसदी का अंतर आने के कारण 2019-20 के लक्ष्य की प्राप्ति और दुष्कर हो जाएगी। 15 फीसदी की वृद्धि दर के बजाय अब वांछित वृद्धि दर 29 फीसदी होगी। आने वाले वर्ष में राजकोषीय समावेशन वैसे भी कठिन चुनौती है।

एक सवाल यह भी है कि सरकारी कंपनियों की उधारी कैसे चुकता होगी और आने वाले वर्ष के लेखा में इससे कैसे निपटा जाएगा। सरकारी क्षेत्रों की इस उधारी को सरकार के खाते में दर्शाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.1 फीसदी तक पहुंच चुका होता।

सरकारी क्षेत्र को ऋण के बोझ तले दबाना स्वयं सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तता और सुधार की प्रतिबद्धताओं के प्रतिकूल है। बजट से इतर उधारी के ऐसे संसाधन यह भी दर्शाते हैं कि शासकीय क्षेत्र के सरकारी ऋण पर नजर रखने की जरूरत है।

बजट से इतर उधारी सरकार को अतिरिक्त राहत प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े बेहतर प्रतीत होते हैं। अगर सरकार ने वाकई 2018-19 की अंतिम तिमाही में अपने व्यय में 1.45 लाख करोड़ रुपये की कटौती की होती तो यह चौथी तिमाही के जीडीपी अनुमान में सरकारी व्यय के आंकड़ों में नजर आता।

यह सही है कि 13,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कम किया गया लेकिन शेष 1.32 लाख करोड़ रुपये वाली बात हकीकत नहीं है। इस व्यय को सरकारी संस्थानों पर डाल दिया गया।चौथी तिमाही में सरकारी व्यय 13 फीसदी से अधिक बढ़ा। अगर सरकार ने वास्तव में व्यय में कटौती की होती तो सरकार की व्यय वृद्धि इतनी अधिक नहीं होती और जनवरी-मार्च 2019 तिमाही में जीडीपी वृद्धि के आंकड़े 5.8 फीसदी से कम रहते।

इसमें दो राय नहीं कि 2018-19 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने का जो जादू हुआ है, उसके कई कारक परेशान करने वाले हैं।

कानाफूसी

मोदी की तारीफ

'23 मई को राजनीतिक मौसम नहीं बल्कि देश की राजनीति की जलवायु ही बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत एक नौसिखुआ की तरह की थी लेकिन अपनी दूसरी पारी की शुरुआत वह एक राज्याध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं। 20वीं सदी का भारत जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मोदी शायद 21वीं सदी के भारत के निर्माता बनने की नियति लेकर आए हैं। मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बड़े बहुमत के साथ लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे दो अन्य नेता जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की श्रेणी में हैं।' आपको कोई अंदाजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये सारी बातें किसने कहीं? ये कहने वाले हैं देश के पूर्व विदेश मंत्री और कम से कम तीन दशक तक कांग्रेस पार्टी में अत्यंत अहम दर्जा रखने वाले नेता कुंवर नटवर सिंह।

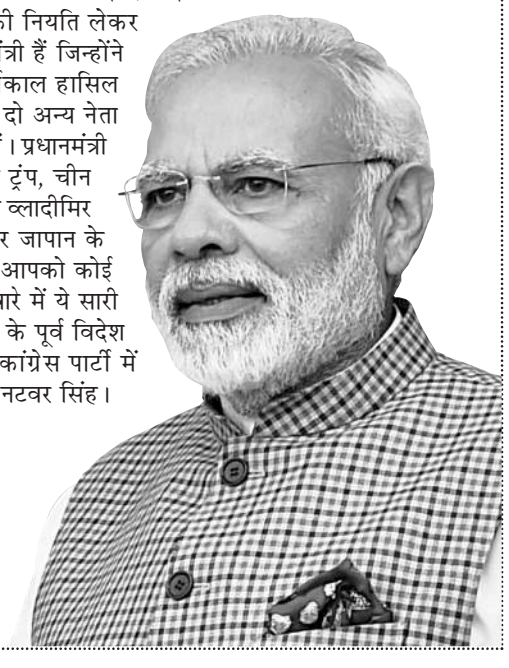

आपका पक्ष

वायु प्रदूषण विश्व की मुख्य चिंता

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम बीट द एयर पलूशन थी। इस दिवस का महत्त्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से यह दिवस मनाया जा रहा है जिससे दुनिया में पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता लाई जा सके। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 में से 9 व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। सयुंक्त राष्ट्र ने वायु प्रदूषण से होने वाले कुछ मुख्य कारण बताए हैं जिसमें घरेलू कार्यों से होने वाला वायु प्रदूषण, वाहनों से, खेत में फसल जलाने से, कारखानों से निकलने वाला धुआं आदि हैं। इन वजहों से लोगों को दमा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा और वायु प्रदूषण के कारण दमा की बीमारी बच्चों में भी देखने मिल रही है। पर्यावरण रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और बढ़ती आबादी की वजह से वन्य क्षेत्र मानव द्वारा

तबाह किए जा रहे हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। पेड़ों की कमी के चलते हवा में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों के लिए चीन बेहिसाब कोयले को

पर्यावरण को बचाने तथा स्वच्छ वायु के लिए लोगों को पेड़ लगाने की जरूरत है

जलाता है। इसका असर उसके पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो सबसे जिम्मेदार देश कहलाता है यह कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। सेंटर फॉर ग्लोबल की एक चेतावनी के अनुसार अगर पेड़ घटने की दर तेजी से जारी रही तो वर्ष 2050 तक विश्व मानचित्र में भारत के क्षेत्रफल के बराबर पेड़ समाप्त हो जाएंगे। पेड़ की कमी के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसलिए वायु प्रदूषण को सही मायने में कम करने के लिए पौधरोपण अभियान और इसकी देखरेख का अभियान चलाना जरूरी है। देश में पौधरोपण अभियान तो आए दिन चलते हैं लेकिन उसकी देखरेख नहीं होने से पौधा कभी वृक्ष नहीं बन पाता है। जब धरती 32 प्रतिशत वन्य क्षेत्र से घिरी होगी तभी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और पर्यावरण दिवस का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

मॉनसून की दस्तक उठाने होंगे कदम

मॉनसून ने केरल के तट पर बीते शनिवार को दस्तक दे दी है। इसके साथ ही धीरे-धीरे पूरे देश में बारिश होगी। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने के साथ ही देश के कई जगहों में पेयजल संकट से भी निजात मिलने की उम्मीद है। मॉनसून के आने के साथ ही सरकार तथा लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बारिश का जल संचय करने के लिए सरकार के साथ लोगों को भी कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार ने जल संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित नियम तो बनाए हैं लेकिन नियमों से ऊपर उठ कर लोगों को खुद जल संचयन करना होगा। अगर अगले साल सूखे जैसी स्थिति से निजात पाना है तो लोगों को इस बारिश से जल संचय करना होगा। केवल सरकार की जिम्मेदारी कह कर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लोगों को छोटे स्तर पर ही जल संचय करना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।